उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल।

आपराधिक संशोधन सं0–211/2019

मास्टर श्रेष्ठा, नाबालिग उम्र करीब 6 वर्ष, पुत्र श्री विवेक स्वरूप।

.....याचिकाकर्ता।

बनाम

उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य .....उत्तरदाता।

अधिवक्ताः– श्री सुधीर कुमार, अधिवक्ता याचिकाकर्ता।
श्री सचिन पंवार, संक्षिप्त धारक उत्तराखण्ड राज्य।
श्री ललित शर्मा, अधिवक्ता उत्तरदाता सं0 2।

माननीय शरद कुमार शर्मा, जे.।

हालांकि यह आपराधिक पुनरीक्षण एक बहुत ही सीमित प्रतीत होता है, सीमित संभावना, जहां संशोधनवादी ने आंशिक चुनौती की मांग की थी दिनांक 12.04. 2019 का आक्षेपित आदेश, जो न्यायाधीश, परिवार द्वारा पारित किया गया है कोर्ट हल्द्वानी, जिला नैनीताल विविध में। 2014 का केस नंबर 33, मास्टर श्रेष्ठ बनाम विवेक स्वरूप, जिससे एक आवेदन की औचित्य पर विचार करते हुए जिसे दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत वरीयता दी गई थी। भरण–पोषण राशि प्रदान करने बाबत जिसे पुनरीक्षणकर्ता द्वारा रु. 30,000/– प्रति की दर से भुगतान किए जाने का दावा किया गया था प्रतिमाह, रुपये रु. 10,000/– प्रति की दर से देय होना निर्धारित किया गया है महीने के आक्षेपित आदेश द्वारा, जिसे चुनौती दी जा रही है कि प्रार्थना की जाए कि आदेश की तिथि के बजाय आवेदन की तिथि से ही किया जा सकता है। विभिन्न विषयों के तहत कई अन्य संपार्श्विक कार्यवाही हुई थी, जो पार्टियों द्वारा संशोधन के लिए तैयार किए गए थे, लेकिन यह प्रासंगिक नहीं हो सकता है इस आपराधिक पुनरीक्षण का निर्णय करते समय इस स्तर पर इस न्यायालय द्वारा विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत एक बच्चे के भरण–पोषण के मुद्दे को अलग जटिलता और रंग ही जो स्वतंत्र रूप से होना है। माना

जाता है और विशेष रूप से वर्तमान मामले के तथ्यों के तहत जहां संशोधनवादी का प्रतिवादी संख्या 2 का जैविक पुत्र होने का विवाद था एक तथ्य जो इस न्यायालय द्वारा पारित न्यायिक आदेश द्वारा स्थापित किया गया था। इसलिए, अब कोई विवाद नहीं रह गया है कि संशोधनवादी का जैविक पुत्र है प्रतिवादी संख्या 2 यहाँ।

2. संशोधनवादी ने आंशिक देते हुए इस संशोधन को प्राथमिकता दी थी चुनौती के तहत आक्षेपित आदेश को चुनौती अर्थात दिनांक 12.04.2019, प्रार्थना रखरखाव के अनुदान में वृद्धि के लिए, जैसा कि द्वारा निर्धारित किया गया है न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, सहित समग्र परिस्थितियों पर विचार करते हुए संबंधित संपत्तियों, संबंधित देनदारियों से संबंधित पहलू, जो या तो पार्टियों के यानी संशोधनवादी के माता–पिता को और आय को पूरा करना है जो संशोधनवादी के माता–पिता के लिए जमा हो रहा है। इस लंबे ड्रा में आपराधिक पुनरीक्षण की कार्यवाही में दलील और प्रतिवाद किया गया था पक्षकारों द्वारा रिकॉर्ड पर रखी गई दलीलें और कुछ तथ्य, जो अब कायम हैं स्वयं अभिवचनों के आधार पर अखंडित और स्थापित हैंः –

i. यह कि प्रतिवादी संख्या 2, जो बच्चे का जैविक पिता है पुनरीक्षणवादी एक आयकर दाता है और उसने अपनी आयकर विवरणी प्रस्तुत कर दी है उसकी वार्षिक आय दिखाते हुए, उसे रु. 12,00,000/– प्रति वर्ष अर्थात 1,00,000/– रुपये प्रति माह के बराबर।

ii. पुनरीक्षणवादी के वकील ने प्रस्तुत किया है कि विभिन्न कारणों से देनदारियां, जो वर्तमान संशोधनवादी के अभिभावक को खाते में चुकानी पड़ती हैं पहले के पति के साथ उसके पूर्व वैवाहिक कलह के बारे में, उसे भी करना होगा पहले विवाह से पैदा हुए अन्य दो बच्चों का भरण–पोषण करें।

iii. कि बीच की अवधि के दौरान, चूंकि वह यानी एचटीई की मांध्अभिभावक पुनरीक्षणवादी ने वकालत पूरी कर ली है और अब वह जिले में अधिवक्ता की प्रैक्टिस कर रहा है हल्द्वानी की अदालत, वह बहुत स्नेहक अभ्यास नहीं कर रही है और उसके पास है 12.04.2022 को पुनरीक्षणकर्ता द्वारा दायर शपथ पत्र के पैरा 6 में निवेदन किया गया, जिसमें यह दावा किया गया है, कि उसकी केवल लगभग आय हो

रही है रु. 10,000/– प्रति माह और आयकर दाता नहीं है और उसका मूल्यांकन नहीं किया गया है जैसे कि आयकर अधिनियम के तहत।

3. दूसरी ओर, प्रतिवादी संख्या 2 के वकील के पास था ने कहा कि प्रतिवादी पर कोई अतिरिक्त वित्तीय बोझ नहीं डाला जा सकता है नंबर 2–पति भरण–पोषण राशि बढ़ाकरय उस कारण से उसे अपने वृद्ध माता–पिता का पालन–पोषण करना पड़ता है, इस तथ्य के साथ कि एक और आधार बचाव, जो प्रतिवादी संख्या 2 ने लिया है, वह उसका अभिभावक है संशोधनवादी यानी उनकी मां ज्योति, आर्थिक रूप से सक्षम हैं और कहा जाता है कि उनका अपना आवास है, जिसे उन्होंने अपनी तिजोरी से खरीदा है, एक चार पहिया वाहन भी शामिल है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसे खरीदा गया था उसे एक डाउन पेमेंट करके जो कि अपने आप में एक तथ्य है, जो उसे स्थापित करता है संशोधनवादी बनाए रखने के लिए वित्तीय दायित्व, जिसके लिए वह भी बराबर है जवाबदार।

4. इस न्यायालय का विचार है कि जहां तक दोनों की जिम्मेदारी है संशोधनवादी के माता–पिता का संबंध है, यह प्रकृति में न्यायसंगत है, एक होने के नाते जैविक पिता और माता, दोनों को बनाए रखने की समान जिम्मेदारी होती है उनके द्वारा नाबालिग बच्चे को पृथ्वी पर लाया गया। लेकिन एक नाबालिग बच्चे का भरण–पोषण होता है हमेशा प्रचलित बाजार स्थितियों, मुद्रास्फीति के अनुरूप होना चाहिए दर और एक प्रत्याशित निवेश, जो एक बेहतर और के लिए किए जाने की आवश्यकता है बच्चे की आरामदायक परवरिश और शिक्षा के बारे में ये सभी पहलू और बच्चे की उचित परवरिश माँ की समान जिम्मेदारी है, साथ ही पिता प्रतिवादी संख्या 2, यहाँ।

5. प्रतिवादी संख्या 2 के लिए विद्वान वकील का तर्क, से संभावित, कि संशोधनवादी की प्राकृतिक माँ उतरी है, जैसा कि इस तरह की एक कार अपने आप में कोई तर्क नहीं दे सकती है, जिसका लाभ उठाया जा सकता है प्रतिवादी नंबर 2–पति को रखरखाव के उचित भुगतान से इनकार करने के लिए संशोधनवादी, जो उसे होने वाली आय के अनुरूप होना चाहिए। केवल इसलिए कि मां के पास संपत्ति है, वह खुद नहीं हो सकती दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत रखरखाव से इन्कार करने का एक वैध कारण हो। लेकिन वर्तमान मामले की परिस्थितियों को

देखते हुए जो लाया गया है रिकॉर्ड, इस न्यायालय का विचार है कि इस तथ्य पर विचार करते हुए, कि तारीख के बाद से दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत आवेदन की संस्था। यानी पर 10.01.2014, रुपये 10,000/– प्रति की दर से रखरखाव का निर्धारण माह, जिसे आक्षेपित आदेश द्वारा भुगतान करने का निर्णय लिया गया है, जो कि है बढ़ाने की मांग की गई है, की तारीख से देय होना चाहिए आवेदन स्वयं और फैसले की तारीख से नहीं, जैसा कि इसे प्रदान किया गया है फैमिली कोर्ट द्वारा 12.04.2019 को। यह सिद्धांत तय किया गया है, कि की धारा 125 के तहत नाबालिग बच्चे को देय भरण–पोषण का निर्धारण सी.आर.पी.सी. या उस प्रयोजन के लिए भी आवेदन के आवेदक के तहत धारा 125 सी.आर.पी.सी. यह उस तारीख से देय होने के लिए निर्धारित किया जाना है जब आवेदन दायर किया गया है जो कि तत्काल मामले में होता है 10.01.2014 का।

6. संशोधनवादी वकील द्वारा व्यक्त की गई शिकायत यह है कि हालांकि की दर से पुनरीक्षणकर्ता को भुगतान किए जाने वाले भरण–पोषण का निर्धारण रुपये 10,000/– की तिथि से देय करने का निर्देश दिया गया है निर्णय, स्पष्ट रूप से खराब है क्योंकि, यदि किसी रखरखाव की आवश्यकता होती है निर्धारित, इसे 10.01. 2014 से देय होना चाहिए था। मैं कोई कारण नहीं देखते, विश्वास नहीं करते और द्वारा बढ़ाए गए तर्क को स्वीकार करते हैं द्वारा निर्धारित रखरखाव का भुगतान करने के लिए पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान वकील फैमिली कोर्ट ने आवेदन की तारीख से और इस तरह का फेसला 12.04.2019 को 10,000/– रुपये की दर से देय होने वाले रखरखाव का निर्धारण 10.01.2014 से यानी की तारीख से देय माना जाएगा आवेदन को दाखिल करना और फैसले की तारीख से नहीं। इसलिए 10.01.2014 से 10.01. 2014 तक की अवधि के लिए रु. 10,000/– प्रति माह की दर से बकाया 11.04. 2019, यानी फेसले की तारीख, प्रतिवादियों द्वारा एक के रूप में भुगतान किया जाएगा आज के फैसले के परिणामस्वरूप दो महीने की अवधि के भीतर बकाया आज से।

7. मुख्य मुद्दे पर वापस लौटनाय जहां संशोधनवादी ने चाहा है की धारा 125 के तहत भरण–पोषण के भुगतान में वृद्धि दण्ड प्रक्रिया संहिता इस न्यायालय का विचार है, कि संबंधित के लिए एक पृथक व्याख्या अभिभावक को प्राप्त होने वाली आय एक विशिष्ट पैरामीटर नहीं हो सकती है, जो हो सकती है रखरखाव की पर्याप्तता निर्धारित करने के लिए नींव होना निर्धारित किया जाना चाहिए, जो एक बच्चे को देय

होगा क्योंकि रखरखाव हमेशा एक होता है कई परिवेश परिस्थितियों के आधार पर परिवर्तनीय कारक, और सहित कारण, जीवन स्तर में आनुपातिक वृद्धि और दामों मे वृद्धि। चूंकि वर्तमान मामले में इस बात को स्वीकार किया गया है कि इसमें कोई सामग्री नहीं है उत्तरदाताओं द्वारा अपनी आय के तथ्य से इनकार करने के लिए लाए गए रिकॉर्ड के विपरीत, 12,00,000/– रुपये प्रति वर्ष की दर से अपने स्वयं के आयकर के अनुसार अर्जित करना वापस करना, कौन है ए तथ्य नहीं निश्चित रूप से मुकाबला अधिक खासकर जब प्रतिवादीधपिता द्वारा उठाए गए तर्क के तथ्य का खंडन करने में सक्षम नहीं है माँ इस आशय से कि पत्नी, संशोधनवादी की संरक्षक के पास है केवल रु. 10,000/– प्रति माह की आय।

8. इस न्यायालय का मत है कि जब दायित्व, जो प्रतिवादी संख्या 2 को अपना और वृद्ध का भरण–पोषण करने के अलावा झेलना पड़ता है माता–पिता, उसे बनाए रखने के लिए बोझ को समान रूप से और उचित रूप से साझा करना होगा बच्चे और प्रतिद्वंद्वी विवादों पर विचार करने के बाद इक्विटी को संतुलित करने के लिए विभिन्न संभावनाओं से, पहले ही ऊपर चर्चा की जा चुकी है, इस न्यायालय का विचार है कि 10,000/– रुपये के रखरखाव का निर्धारण जैसा निर्धारित किया गया है सीखा परिवार न्यायालय, वास्तव में कोई प्रशंसनीय तर्क नहीं था, जो रहा है इसे निर्धारित करने के लिए अपनाया गया और समग्र परिदृश्य पर विचार किया गया पल, इस न्यायालय का विचार है, कि यह न्याय और इच्छा के सिरों को पूरा करेगा यदि रखरखाव की राशि है, तो पार्टियों के बीच भी इक्विटी को संतुलित करें 10,000/– रुपये से बढ़ाकर 15,000/– रुपये, जिसका भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा, पुनरीक्षणकर्ता को प्रत्येक माह की 10 तारीख तक। इस प्रकार राशि आज के आदेश से बढ़ाने के लिए निर्देशित, जाहिर तौर पर एक वृद्धि होगी, जिसे 29.04.2019 से लागू किया जाएगा, यानी जब से पुनरीक्षणवादी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण को प्राथमिकता दी गई थी और बकाया, जो 15,000/– रुपये की दर से प्रोद्भूत होता है, अर्थात 5,000/– रुपये प्रति माह का अंतर दिनांक 29.04.2019 से आज तक अर्थात 21.04.2022 तक की अवधि के लिए भी सुनिश्चित किया जायेगा। प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा पुनरीक्षणकर्ता को दो की अवधि के भीतर भुगतान किया जाना है इस फैसले की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तारीख से महीने।

9. की दर से देय होने वाले भरण–पोषण का निर्धारण रु. 15,000/– प्रति माह, जैसा कि ऊपर निर्देशित किया गया है, के अधिकारों पर ध्यान दिए बिना होगा उपयुक्त संशोधन की तलाश के लिए किसी भी पक्ष का सहारा लिया जाए या एक उपयुक्त कार्यवाही दाखिल करके निर्धारित रखरखाव में सुधार जैसा कि पहले दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के तहत अनुमेय है उपयुक्त न्यायालय।

10. उपरोक्त कारणों के अधीन, आपराधिक पुनरीक्षण आंशिक रूप से होता है अनुमति दी जाती है और विवादित आदेश उस सीमा तक संशोधित माना जाएगा।

(शरद कुमार शर्मा, जे.)

21.04.2022